

रजिस्टर्ड नं० एल०-३३/एस० एम०/१३-१४/९६.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, २ दिसम्बर, १९९६/११ अग्रहायण, १९१८

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-१७१००४, २ दिसम्बर, १९९६

संख्या १-५८/९६-वि० स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली १९७३ के नियम १३५ के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, १९९६ (१९९६ का विधेयक

३५८७-राजपत्र/९६-२-१२-९६—१,२३१.

(५३५१)

मूल्य : १ रुपया ।

संख्यांक 25) जो दिनांक 2 दिसम्बर, 1996 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थानित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ असाधारण राजपत्र में मद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित/-

सचिव ।

1996 का विधेयक संख्यांक 25.

हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 1996

(विधान सभा में यथा पुरः स्थापित)

राज्य महिला आयोग का गठन करने और उससे संश्लेषित या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 द्वारा गारन्टीकृत महिलाओं से सम्बन्धित मूल अधिकारों को अग्रसर करने के प्रयोजन से और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों, विशिष्टतया, जो संविधान के अनुच्छेद 38, 39, 39-क और 42 में प्रतिष्ठापित हैं, को कार्यान्वित करने, समाज में महिलाओं की हैसियत और गरिमा में सुधार लाने, महिलाओं के प्रति अपमानजनक व्यवहार के विरुद्ध अन्वेषण करने और उपयुक्त उपचारात्मक उपाय करने या सुझाव देने, महिलाओं को प्रभावित करने वाली विधि को प्रभावशाली मानिटर और कार्यान्वित करने तथा समाज में महिलाओं की हैसियत और गरिमा से सम्बन्धित सुधार और उत्थान के सभी विषयों पर सरकार को परामर्श देने के लिए आयोग का गठन करने और उसके संश्लेषित या अनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करना समीचीन है।

भारत गणराज्य के संसदीय संवैधानिक ढाँचे में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्न-लिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1996 है। संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है ;

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं

(क) “आयोग” से धारा 3 के अधीन महिलाओं के लिए गठित हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग अभिप्रेत है ;

(ख) “पुलिस महानिदेशक” से हिमाचल प्रदेश राज्य का पुलिस महानिदेशक अभिप्रेत है ;

(ग) “सदस्य” से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष तथा सदस्य-सचिव भी हैं ;

(घ) “राष्ट्रीय महिला आयोग” से राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय महिला आयोग अभिप्रेत है ;

(ङ) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ; और

(च) “महिला” के अन्तर्गत बालिका या किशोरी भी है।

आयोग का
गठन ।

3. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग के नाम से जात एक निकाय का गठन करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदिष्ट कृत्यों का पालन करेगा ।

(2) यह आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा:—

(क) अध्यक्ष, जो महिलाओं के हित के लिए समर्पित विख्यात महिला हो;

(ख) राज्य सरकार द्वारा ऐसे योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट चार गैर-सरकारी सदस्य अधिमानतः महिलाएं, जिन्होंने विधि अथवा विधायन में, महिलाओं की उन्नति सम्बन्धी विषयों के प्रशासन या महिलाओं की सुरक्षा, उत्थान और सामान्य हितों की अभिवृद्धि के लिए उनके हितों की पूर्ति की है या किसी व्यवसाय, संघ या स्वैच्छिक महिला संगठन के नेतृत्व का प्रयाप्त अनुभव है ;

परन्तु उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में से क्रमशः प्रत्येक का कम से कम एक सदस्य होगा ;

(ग) आयुक्त एवं सचिव (कल्याण) और पुलिस महानिदेशक आयोग के पदेन सदस्य होंगे ;

(घ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला सदस्य-सचिव, ऐसा अधिकारी होगा जो राज्य की सिविल सेवा या भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य रहा हो या राज्य के अधीन सिविल पद धारण करता हो ।

अध्यक्ष और
सदस्यों की
पदावधि और
सेवा शर्तें ।

4. (1) अध्यक्ष और प्रत्येक गैर-सरकारी सदस्य तीन वर्ष से अधिक ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे ।

(2) अध्यक्ष या गैर-सरकारी सदस्य, राज्य सरकार को सम्बोधित लेख द्वारा किसी भी समय, अध्यक्ष या सदस्य का पद त्याग सकेगा ।

(3) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, किसी व्यक्ति को, अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा सकेगी, यदि वह व्यक्ति—

(क) अनुमोचित दिवालिया हो जाता है ;

(ख) ऐसे किसी अपराध जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्गस्त है के लिए सिद्धदोष ठहराया और कारावास से दण्डादिष्ट किया जाता है ;

(ग) विकृतचित्त हो जाता है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है ;

(घ) कार्य करने से इन्कार करता है या कार्य करने में प्रसमर्थ हो जाता है ;

(ङ) आयोग की लगातार तीन बैठकों से, आयोग से अनुपस्थित रहने की इजाजत लिए बिना अनुपस्थित रहता है ; या

(च) अध्यक्ष या सदस्य के पद का इस प्रकार दुरुपयोग करता है कि राज्य सरकार की राय में ऐसे व्यक्ति का उस पद पर बना रहना लोकहित के लिए अहितकर है या ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अन्यथा वह अयोग्य या अनुपयुक्त है :

परन्तु इस छण्ड के अधीन किसी व्यक्ति को तब तक, जब तक कि उस व्यक्ति को इस विषय में सुनवाई का उचित अवसर नहीं दे दिया जाता, नहीं हटाया जाएगा ।

(4) उप-धारा (2) या (3) के अधीन या किसी अन्य रीति में, होने वाली रिक्ति, यथाशक्य शीघ्र, राज्य सरकार द्वारा नए नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी, और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, उस व्यक्ति की शेष पदावधि के लिए पद धारण करेगा जिसकी रिक्ति में ऐसे व्यक्ति का नाम निर्देशन किया गया है, और यदि रिक्ति न हुई हो, तो वह व्यक्ति उस पद पर रहता :

परन्तु यदि अध्यक्ष से भिन्न किसी सदस्य की रिक्ति उस तारीख, जिसको उस सदस्य की पदावधि का अवमान होगा, से पूर्ववर्ती तारीख के छः मास के भीतर होती है, तो रिक्ति भरी नहीं जाएगी ।

(5) अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन, मानदेय, यदि कोई हो और भत्ते तथा उन पदों को धारण करने के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं ।

5. (1) राज्य सरकार आयोग के लिए ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो, राज्य सरकार की राय में, इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हों ।

आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ।

(2) आयोग के प्रयोजनों के लिए नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते और उनकी अन्य सेवा निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं ।

6. अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन, मानदेय और भत्ते तथा प्रशासनिक व्यय, जिसके अन्तर्गत धारा 5 में निर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन भी है, धारा 16 में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदत्त किए जाएंगे ।

अनुदान में से वेतन मानदेय और भत्तों का संदत्त किया जाना ।

7. आयोग का कोई भी कार्य या कार्यवाही आयोग में कोई रिक्ति विद्यमान होने या उसके गठन में कोई त्रुटि होने अथवा अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्यरत किसी व्यक्ति के नामनिर्देशन में त्रुटि होने या बैठक करने के लिए नोटिस जारी करने सहित आयोग की प्रक्रिया में किसी अनियमितता, जो विषय के गुणागुण को प्रभावित न करे, के आधार पर हो प्रश्नगत या अविधिमान्य नहीं होगी ।

रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।

आयोग की समितियां। 8. (1) आयोग ऐसी समितियां नियुक्त कर सकेगा जो इसके कृत्यों, शक्तियों और कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन, प्रयोग और निर्वहन करने तथा ऐसे विशेष प्रश्नों पर जो आयोग द्वारा समय-समय पर उठाए जाएं, विचार करने के लिए आवश्यक हों।

(2) आयोग को उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त किसी समिति में, एक या अधिक व्यक्तियों को, जितने वह उचित समझे, सहयोजित करने की शक्ति होगी और ऐसा व्यक्ति/ऐसे व्यक्तियों को, जो आयोग के सदस्य नहीं हैं, समिति की बैठकों में उपस्थित रहने तथा उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(3) इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति समिति की बैठकों में उपस्थित होने और समिति के अन्य कार्य पर हुए व्यय के लिए ऐसे भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे जो विहित किए जाएं।

(4) आयोग ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो वह आवश्यक समझे, राष्ट्रीय महिला आयोग के किसी प्रतिनिधि को अपनी किसी बैठक में आमन्त्रित कर सकेगा या किसी व्यक्ति को, जिसकी सहायता या सलाह इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन करने में अथवा इस अधिनियम के अधीन इसके किन्हीं कृत्यों को कार्यान्वित करने में आवश्यक समझता है, अपने साथ सहयुक्त कर सकेगा और इस प्रकार आमन्त्रित या सहयुक्त व्यक्ति को, उस प्रयोजन से सुसंगत, जिसके लिए ऐसे प्रतिनिधि या व्यक्ति को आमन्त्रित या सहयुक्त किया गया है, आयोग की चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु मत देने का अधिकार नहीं होगा।

प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना। 9. (1) आयोग या उसकी समिति की बैठक, जब भी आवश्यक हो, की जाएगी और वह ऐसे समय और स्थान पर की जाएगी जो अध्यक्ष ठीक समझे।

(2) आयोग अपनी प्रक्रिया तथा अपनी समितियों की प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा।

(3) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सदस्य-सचिव द्वारा या इस निमित्त सदस्य-सचिव द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधि-प्रमाणित किए जाएंगे।

आयोग के कृत्य।

10. (1) आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—

(क) संविधान और अन्य विधियों के अधीन महिलाओं के लिए उपयुक्त रक्षोपायों से सम्बन्धित सभी विषयों का अन्वेषण और परीक्षण करना ;

(ख) उन रक्षोपायों के बारे में प्रति वर्ष और ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे, राज्य सरकार को रिपोर्ट देना ;

(ग) ऐसी रिपोर्टों में, महिलाओं की दशा सुधारने के लिए राज्य द्वारा उन रक्षोपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें करना ;

(घ) संविधान और अन्य विधियों के, महिलाओं को प्रभावित करने वाले, विद्यमान उपबन्धों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उनमें

संशोधनों जिससे कि ऐसे विधानों में किसी कमी, अपर्याप्तता या त्रुटियों को दूर करने के लिए उपचारी विधायी उपायों का सुझाव दिया जा सके, की सिफारिश करना ;

(ड) महिलाओं से सम्बन्धित संविधान और अन्य विधियों के उपबन्धों के अतिक्रमण के मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना ;

(च) निम्नलिखित से सम्बन्धित विषयों पर शिकायतें प्राप्त करना और स्वप्रेरणा से ध्यान देना:—

(i) महिलाओं के अधिकारों का बंचन ;

(ii) महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने और समता तथा विकास का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए भी अधिनियमित विधियों का अक्रियान्वयन ;

(iii) महिलाओं की कठिनाईयों को कम करने और उनका कल्याण और विकास सुनिश्चित करने तथा उनको अनुतोष उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ नीतिगत विनिश्चयों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या अनुदेशों का अननुपालन और ऐसे विषयों से उद्भूत प्रश्नों को राज्य सरकार या समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना ;

(छ) महिलाओं से सम्बन्धित सांविधानिक और किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिक्रमण की दशा में किसी न्यायिक मंच या अधिकरण में कार्यवाही संस्थित करने के लिए निर्धन महिलाओं का मार्गदर्शन करना और सलाह देना ;

(ज) महिलाओं के विरुद्ध विभेद और अत्याचारों से उद्भूत विनिर्दिष्ट समस्याओं या स्थितियों का विशेष अध्ययन या अन्वेषण कराना और बाधाओं का पता लगाना जिससे कि उनके निराकरण के लिए कार्य योजनाओं की सिफारिश की जा सके ;

(झ) संवर्धन और शिक्षा सम्बन्धी अनुसंधान करना जिससे कि महिलाओं का सभी क्षेत्रों में सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव दिया जा सके और उनको उन्नति में अड़चन डालने के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाना जैसे कि आवास और बुनियादी सेवाओं की प्राप्ति में कमी, उबाऊपन और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य परिसंकटों को कम करने के लिए सहायक सेवाओं और प्रौद्योगिकी अपर्याप्तता ;

(ञ) महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना ;

(ट) राज्य में महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना ;

(ठ) किसी जेल, सुधारगृह, महिलाओं की संस्था या अभिरक्षा के अन्य स्थान का, जहां महिलाओं को बन्दी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है, निरीक्षण करना या करवाना और उपचारी कार्रवाई के लिए, ऐसे विषयों को जो आवश्यक पाए जाएं, सम्बन्धित प्राधिकारियों से बातचीत करना ;

(ड) पुलिस शिकायतों सहित बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नों या महिलाओं को प्रभावित करने वाले संविधान अथवा किन्हीं अन्य विधियों के उपबन्धों के निर्वाचन के लिए धन उपलब्ध कराना, और प्रत्येक छः मास में ऐसे विषयों से सम्बन्धित रिपोर्ट, राज्य सरकार को प्रस्तुत करना ;

(ढ) महिलाओं से सम्बन्धित किसी बात और विशिष्टतया उन विभिन्न कठिनाईयों के बारे में जिनके अधीन महिलाएं कार्य करती हैं, सरकार को नियतकालिक रिपोर्ट देना ;

(ण) राष्ट्रीय महिला आयोग और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा स्थापित अन्य महिला आयोगों को तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग तथा अल्पसंख्यक आयोग को भी सहयोग देना और उनकी सहायता करना तथा उनसे सहयोग और सहायता प्राप्त करना ;

(त) इस अधिनियम के अधिक प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार या किसी अन्य समुचित प्राधिकारी के विचारार्थ स्कीमें तैयार करना और विशिष्टतया, अभित्यक्त महिलाओं को भरण-पोषण के संदाय, न्यूनतम मजदूरी का संदाय, महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन, आवास और आश्रय स्थल, घरेलू हिंसा के निवारण, काम के समय यौन उत्पीड़न, महिलाओं के अवैध दुर्व्यापार का निवारण, महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार और महिलाओं के लिए विधिक सहायता से सम्बन्धित विधियों के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए स्कीमें तैयार करना ; और

(थ) कोई अन्य विषय जिसे राज्य सरकार या राष्ट्रीय महिला आयोग उसे निर्दिष्ट करे ।

(2) राज्य आयोग को, उप-धारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (च) के उप-खण्ड (i) और उप-खण्ड (ii) में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में वे सभी शक्तियां होंगी जो बाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की हैं ; अर्थात्:—

(क) राज्य के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यापेक्षा करना ;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना ; और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए ।

(3) (क) उप-धारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (च) के उप-खण्ड (i) और उप-खण्ड (ii) के अधीन उल्लिखित किसी अन्वेषण के पूरा होने पर, आयोग द्वारा उप-धारा (1) के खण्ड (ड) या (च) के अधीन राज्य सरकार या समुचित प्राधिकारी के पास विषय को उठाए जाने पर, यथा-स्थिति राज्य सरकार या समुचित प्राधिकारी को इस विषय में विधिक कार्यवाही या अभियोजन संस्थित करने की सिफारिश कर सकेगा और राज्य सरकार या समुचित प्राधिकारी को ऐसी किसी विधिक कार्यवाही या अभियोजन के संचालन के लिए काउन्सिल या विशेष अभियोजक नियुक्त करने की भी सिफारिश कर सकेगा और राज्य सरकार, मामले की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और इसका समाधान हो जाने पर कि, इसकी राय में, ऐसा करना आवश्यक है, एक काउन्सिल या विशेष अभियोजक नियुक्त कर सकेगी।

(ख) राज्य सरकार या समुचित प्राधिकारी यथास्थिति, समय-समय पर, आयोग की सिफारिश पर दायर किए गए ऐसी किसी विधिक कार्यवाही या अभियोजन की प्रगति लिखित में आयोग को संसूचित करेगा।

(4) राज्य सरकार या समुचित प्राधिकारी, आयोग से लिखित रूप में पूर्व परामर्श के बिना उप-धारा (3) के अधीन संस्थित ऐसे किसी मामले या कार्यवाहियों को वापस लेने के लिए आवेदन नहीं करेगा।

11. राज्य सरकार, महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी मुख्य नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी।

सरकार का
आयोग से
परामर्श।

12. (1) आयोग, इस अधिनियम के अधीन अन्वेषणों का संचालन करने के लिए, निम्नलिखित सेवा का उपयोग कर सकेगा:—

अन्वेषण का
संचालन
करने के
लिए कतिपय
अधिकारियों
और अन्वेषण
अभिकरणों
की सेवा का
उपयोग करने
की, आयोग
की शक्ति।

(क) राज्य या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण का, उस सरकार की सहमति से; या

(ख) किसी अन्य व्यक्ति ;

(2) किसी अन्वेषण का संचालन करने के लिए, उप-धारा (i) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई अधिकारी या अभिकरण, आयोग के निदेश और नियन्त्रण के अधीन रहते हुए,—

(क) किसी व्यक्ति को समन और हाजिर तथा शपथ पर उसकी परीक्षा कर सकेगा ;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा ; और

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यापेक्षा कर सकेगा ;

(3) ऐसा अधिकारी या अभिकरण अथवा व्यक्ति आयोग द्वारा यथानिर्देशित विषय का अन्वेषण करेगा और उस पर अपनी रिपोर्ट (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस धारा में “अन्वेषण रिपोर्ट” के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) आयोग को ऐसी अवधि

या बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो इस निमित्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट की जाए या बढ़ाई जाए, प्रस्तुत करेगा।

(4) आयोग उप-धारा (3) के अधीन, उसे प्रस्तुत की गई अन्वेषण रिपोर्ट में कथित तथ्यों की शुद्धता और परिस्थितियाँ यदि कोई हों, के बारे में अपना समाधान करेगा और इस प्रयोजन के लिए आयोग ऐसी जांच (जिसके अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है/हैं जिम्मे/जिन्होंने अन्वेषण का संचालन किया है या अन्वेषण में सहायता की है) कर सकेगा जो वह उचित समझे।

व्यक्तियों द्वारा आयोग अथवा धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त व्यक्ति के समक्ष को किया गए साक्ष्य देने के दौरान किया गया कोई कथन, उसे, ऐसे कथन द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के कथन। लिए अभियोजन के सिवाय, किसी सिविल या दाण्डिक कार्यवाही का दायी नहीं बनाएगा या किसी सिविल या दाण्डिक कार्यवाही में उसके विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जाएगा:

परन्तु कथन,—

- (क) ऐसे प्रश्न के अनुरूप किया जाता है, जिसकी आयोग या ऐसे अधिकारी अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा उत्तर में अपेक्षा की जाती है, या
- (ख) अन्वेषण के अधीन विषय-वस्तु से सुसंगत है।

स्वैच्छिक संगठनों का रजिस्ट्रीकरण और उनकी सहायता प्राप्त करना। 14. (1) राज्य में कोई स्वैच्छिक महिला संगठन इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आयोग के पास रजिस्ट्रीकरण करवा सकेगा। आयोग, समाज में ऐसे संगठन के महत्व और भूमिका के बारे में ऐसी रीति में अपना समाधान करने के पश्चात् जैसा आयोग ठीक समझे, ऐसे संगठन का नाम अपने रजिस्टर में सम्मिलित कर सकेगा।

(2) आयोग राज्य में स्वैच्छिक संगठनों और विशिष्टतया महिला संगठनों जिनकी सहायता वह अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए लेना चाहे, का एक रजिस्टर रखेगा।

(3) अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, आयोग राज्य में किसी स्वैच्छिक संगठन, विशिष्टतया महिला संगठनों की सहायता ले सकेगा।

(4) आयोग के पास रजिस्ट्रीकृत ऐसे संगठनों की एक सूची, किसी न्यायालय या प्राधिकारी अथवा अनुगोध करने पर जन-साधारण को उपलब्ध करवाई जाएगी।

(5) यदि आयोग किन्हीं कारणों को अभिलिखित करके अपने रजिस्टर में से किसी संगठन का नाम रद्द करना ठीक समझता है, तो ऐसे संगठन की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, वह ऐसा कर सकेगा।

(6) ऐसे रद्दकरण के बारे में आयोग का विनिश्चय अन्तिम होगा।

मद्भावपूर्वक किए गए कार्य के लिए संरक्षण। 15. इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों अथवा किए गए आदेशों के अनुसरण में मद्भावपूर्वक की गई या की जाने क लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही आयोग के किसी सदस्य या आयोग के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी या राज्य सरकार या आयोग के निदेश के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी।

16. (1) राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोजन के पश्चात्, राज्य को संचित निधि में से ऐसी धनराशि अनुदान के रूप में सौंप करेगी, जैसे राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक समझे।

राज्य सरकार द्वारा अनुदान।

(2) आयोग, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए उतनी धनराशि खर्च कर सकेगा जितनी वह ठीक समझे और वह धनराशि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से सौंपे व्यय माना जाएगा।

17. (1) आयोग समुचित लेखा और अन्य ससंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जो राज्य सरकार, हिमाचल प्रदेश राज्य के महालेखाकार से परामर्श करके, विहित करे।

लेखे और संपरीक्षा।

(2) आयोग के वार्षिक लेखाओं की संपरीक्षा राज्य के महालेखाकार ऐसे अन्तर्गत पर करेगा जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसे संपरीक्षा के सम्बन्ध में उपगत कोई व्यय आयोग द्वारा महालेखाकार को सौंपे होगा।

(3) महालेखाकार और इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के सम्बन्ध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को वही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो महालेखाकार को सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के सम्बन्ध में साधारणतया होते हैं और उसे, विनिर्दिष्टता बहियां, लेखा, सम्बन्धित वाङ्मय और अन्य दस्तावेज तथा कागज-पत्र पेश किए जाने की मांग करने और आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) महालेखाकार या उसके द्वारा सम्यक् रूप से इस निमित्त नियुक्त या प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित आयोग का लेखा और साथ ही उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट आयोग द्वारा राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजी जाएगी।

18. आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रिया-कलापों का पूर्ण विवरण होगा, ऐसे प्रारूप में ऐसे समय पर जो विहित किया जाए तैयार करेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा।

वार्षिक रिपोर्ट।

19. राज्य सरकार, वार्षिक रिपोर्ट और धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख), (ड) और (ड) के अधीन सभी रिपोर्टों/रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवाएगी जिसके साथ, उसमें अन्तर्निहित सिफारिशों पर जहां तक उनका सम्बन्ध राज्य सरकार से है, की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई और ऐसी सिफारिशें यदि कोई हों, संपरीक्षा या रिपोर्ट अस्वीकृत की गई है, तो अस्वीकृति के कारण का ज्ञापन और संपरीक्षा रिपोर्ट भी होगी।

वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जाना।

20. आयोग का अध्यक्ष, उसके सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे।

अध्यक्ष, सदस्यों आदि का लोक सेवक होना।

नियम बनाने की शक्ति । को कार्यान्वित करने के नियम बना सकेंगे ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया या जारी किया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा और यदि, उस सत्र के या आगामी सत्र के अधिसूचना के पूर्व जिसमें इसे इस प्रकार रखा गया है, विधान सभा ऐसे किसी नियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करती है या विधान सभा यह विनिश्चय करती है कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभाव होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई या करने के लिए स्वीकृत किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हमारे देश में अनुभव से यह देखने में आया है कि सरकारी तन्त्र, जब इसका सामना विशेषकर सामाजिक क्षेत्र में, विशेषतया महिला विकास के विकासवात्मक कार्य से होता है, कई प्रकार की समस्याओं से दबा रहता है। इसलिए, महिला सम्बन्धी नीतियों की परीक्षा करने, विधिक रक्षापाथों का पुनर्विलोकन करने, शिकायतों को दूर करने और स्कीमों के कार्यान्वयन का निरीक्षण/मूल्यांकन करने के लिए सर्वोच्च स्तर पर एक उच्च शक्ति सम्पन्न निकाय स्थापित करना अत्यन्त आवश्यक है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए संसद द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 पारित किया गया था। इसके दृष्टिगत राज्य विधान मण्डल कानून के अर्धीन महिलाओं के लिए राज्य स्तरीय महिला आयोग की स्थापना करना आवश्यक समझा गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

विद्याधर,
प्रभारी मन्त्री।

शिबला:

2 दिसम्बर, 1996.

वित्तीय जापन

विधेयक के खण्ड (4) का उप-खण्ड (5) और खण्ड 5 का उप-खण्ड (2) में हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों तथा आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को मानदेय, वेतन और भत्तों के संदाय का उपबन्ध किया गया है। खण्ड 16 के साथ पठित खण्ड 6 के अधीन आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदाय प्रशासनिक व्यय, वेतन और भत्ते, राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान में से संदत्त किए जाएंगे। राज्य महिला आयोग गठित करने के प्रस्ताव पर आरम्भ में 23.41 लाख रुपये व्यय होंगे तथा 16.41 लाख रुपये वार्षिक व्यय होने की सम्भावना है। जिसकी पूर्ति, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से उक्त आयोग को दिए जाने वाले अनुदानों में से की जाएगी।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी जापन

विधेयक का खण्ड 21, इस विधेयक के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। विधेयक के खण्ड 9 के अधीन आयोग द्वारा अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करना अपेक्षित है। राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले नियम विधान सभा के समक्ष रखे जाने हैं। प्रस्तावित प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य स्वरूप का है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[कल्याण विभाग, तस्ति संख्या कल्याण-एफ(2)-2/88-II]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 1996 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

Authoritative English Text

Bill No. 25 of 1996.

**THE HIMACHAL PRADESH STATE COMMISSION FOR WOMEN
BILL, 1996**

AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

BILL

to constitute a State Commission for Women and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS it is expedient to provide for the constitution of a Commission with the aim of furthering the fundamental rights guaranteed by articles 14, 15 and 16 of the Constitution of India with respect to women and to give effect to the Directive Principles of State Policy and in particular those enshrined in Articles 38, 39, 39A and 42 of the Constitution to improve the status and dignity of women in the society, to investigate into and take or suggest suitable remedial measures against practices derogatory to women, to effectively monitor and implement laws affecting women and to advise the Government in all matters related to the improvement and upliftment of status and dignity of women in the society and for matters connected herewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh State Commission for Women Act, 1996.

Short title,
extent and
commence-
ment.

(2) It extends to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

Definitions

(a) “Commission” means the Himachal Pradesh State Commission for Women constituted under section 3;

(b) “Director General of Police” means the Director General of Police, Himachal Pradesh State;

(c) “Member” means a Member of the Commission and includes the Chairperson and the Member-Secretary;

(d) “National Commission for Women” means the National Commission for Women constituted under section 3 of the National Commission for Women Act, 1990;

(e) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act; and

(f) “Women” includes female-child or adolescent girl.

3. (1) The State Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute a body to be known as the Himachal Pradesh State Commission for Women to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to it under this Act.

Constitution
of Commis-
sion.

(2) The Commission shall consist of—

- (a) a Chairperson, who shall be an eminent woman committed to the cause of women;
- (b) not more than four non-official members preferably women, to be nominated by the State Government from amongst the persons of ability, integrity and standing who have served the cause of women or have had sufficient knowledge and experience in law or legislation, administration of matters concerning the advancement of women or leadership of any trade union or voluntary organisation for women for protection, upliftment and promotion of common interests of women :

Provided that, at least one member each shall be from amongst persons belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, respectively ;

- (c) the Commissioner-cum-Secretary (Welfare) and the Director General of Police shall be the *ex-officio* members of the Commission;
- (d) one Member-Secretary, to be nominated by the State Government, shall be any officer, who is or has been a member of the Civil Services of the State or of an All India Service or holds a civil post under the State.

Term of office and conditions of service of Chairperson and Members.

4. (1) The Chairperson and every non-official member shall hold office for such period not exceeding three years as may be specified by the State Government.

(2) The Chairperson or a non-official member may, at any time, by writing and addressed to the State Government, resign from the office of the Chairperson or of the office of the member.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the State Government may remove a person from the office of the Chairperson or member if, that person—

- (a) becomes an undischarged insolvent;
- (b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude;
- (c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court;
- (d) refuses to act or becomes incapable of acting;
- (e) is, without obtaining leave of absence from the Commission, absent from three consecutive meetings of the Commission; or
- (f) in the opinion of the State Government, has so abused the position of the Chairperson or member as to render that person's continuance in office detrimental to the public interest or is otherwise unfit or unsuitable to continue as such Chairperson or member :

Provided that, no person shall be removed under this clause until that person has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(4) A vacancy caused under sub-section (2) or (3) or in any other manner, shall be filled in, as soon as may be, by a fresh nomination by the State Government; and the person so nominated shall hold office for the remainder of the term of office of the person in whose vacancy such person has been nominated and would have held office, if the vacancy had not occurred:

Provided that, if the vacancy of a member other than that of the Chairperson occurs within six months preceding the date on which the term of office of the member expires, the vacancy shall not be filled in.

(5) The salary, honorarium, if any, and allowances payable to, and the other terms and conditions of holding the office of the Chairperson and the members shall be such as may be prescribed.

5. (1) The State Government shall provide the Commission with such officers and employees as, in the opinion of the State Government, may be necessary for the efficient performance of the functions of the Commission under this Act.

Officers and other employees of Commission.

(2) The salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of, the officers and other employees appointed for the purpose of the Commission shall be such as may be prescribed.

6. The salaries, honoraria and allowances payable to the Chairperson and members and the administrative expenses, including salaries, allowances and pensions payable to the officers and other employees referred to in section 5, shall be paid out of the grants referred to in section 16.

Salaries, honoraria and allowances to be paid out of Grants.

7. No act or proceeding of the Commission shall be questioned or shall be invalid on the ground merely of the existence of any vacancy in, or defect in the constitution of the Commission or any defect in the nomination of a person acting as the Chairperson or a member or any irregularity in the procedure of the Commission, including in issuing of notice for holding of a meeting, not affecting merits of the matter.

Vacancies etc. not to invalidate proceedings of Commission.

8. (1) The Commission may appoint such Committees as may be necessary for the efficient performance, exercise and discharge of its functions, powers and duties and also for dealing with such special issues as may be taken up by the Commission, from time to time.

Committees of Commission.

(2) The Commission shall have the power to co-opt one or more persons as it may think fit, on any committee appointed under sub-section (1), and such person or persons, who are not members of the Commission, shall have the right to attend the meetings of the committee and take part in its proceedings, but shall not have the right to vote.

(3) The person so co-opted shall be entitled to receive such allowances towards expenses for attending the meetings and any other task of the Committee, as may be prescribed.

(4) The Commission may invite any representative of the National Commission for Women to any of its meetings, or may associate with itself, in such manner and for such purposes as it may deem necessary, any person whose assistance or advice it may need in complying with any of the provisions of this Act or in carrying out any of its functions under this Act; and a person so invited or associated shall have the right to take part in the discussions of the Commission relevant to the purposes for which such representative or person has been invited or associated, but shall not have the right to vote.

Procedure
to be regulated by
Commission.

9. (1) The Commission or a committee thereof shall meet as and when necessary and shall meet at such time and place, as the Chairperson may deem fit.

(2) The Commission shall regulate its own procedure and the procedure of the committees thereof.

(3) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Member-Secretary or any other officer of the Commission duly authorised by the Member-Secretary in this behalf.

Functions of
Commission.

10. (1) The Commission shall perform all or any of following functions, namely :—

- (a) investigate and examine all matters relating to the safeguards provided, for women under the Constitution and other laws;
- (b) present to the State Government, annually and at such other times, as the Commission may deem fit, reports upon the working of those safeguards;
- (c) make in such reports recommendations for the effective implementation of those safeguards for improving the condition of women by the State;
- (d) review, from time to time, the existing provisions of the Constitution and other laws affecting women and recommend amendments thereto so as to suggest remedial legislative measures to meet any lacunae, inadequacies or shortcomings in such legislations;
- (e) take up the cases of violation of the provisions of the Constitution and of other laws relating to women with the State Government or appropriate authorities;
- (f) entertain complaints and take *suo-moto* notice of matters relating to,—
 - (i) deprivation of women's rights;
 - (ii) non-implementation of laws enacted to provide protection to women and also to achieve the objective of equality and development;
 - (iii) non-compliance of policy decisions, guidelines or instructions aimed at mitigating hardships and ensuring welfare and development and providing relief to women, and to take up the issues arising out of such matters with the State Government or appropriate authorities;

- (g) render guidance and advice to needy women in instituting proceedings in any judicial forum or tribunal for violation of constitutional provisions or any other laws relating to women;
- (h) call for special studies or investigations into specific problems or situations arising out of discrimination and atrocities against women and identify the constraints so as to recommend strategies for their removal;
- (i) undertake promotional and educational research so as to suggest ways of ensuring due representation of women in all spheres and identify factors responsible for impeding their advancement, such as, lack of access to housing and basic services, inadequate support services and technologies for reducing drudgery and occupational health hazards;
- (j) participate and advice on the planning process of socio-economic development of women;
- (k) evaluate the progress of the development of women in the State;
- (l) inspect or cause to be inspected a jail, remand home, women's institution or other places of custody where women are kept as prisoners or otherwise, and take up with the concerned authorities such matters for remedial action as found necessary;
- (m) fund litigation including police complaints involving issues affecting a large body of women or the interpretation of any provision of the Constitution or any other laws affecting women, and present to the State Government, every six months, report relating to such matters;
- (n) make periodical reports to the State Government or any matter pertaining to women and, in particular, various difficulties under which women toil;
- (o) co-operate with and assist and seek co-operation and assistance of the National Commission for Women and other Commissions for Women set up by different State Governments and also the Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the Minorities Commission;
- (p) frame schemes for the consideration of the State Government or any other appropriate authority for more effective implementation of this Act and, in particular, frame schemes for more effective implementation of laws relating to payment of maintenance to deserted women, payment of minimum wages, ensuring equal pay for equal work, housing and shelter for women, prevention of domestic violence, prevention of sexual harassment at work, prevention of illegal traffic in women, improvement of the health and safety in women and legal aid for women; and
- (q) any other matter which may be referred to it by the State Government or by the National Commission for Women.

(2) The State Commission shall, while investigating any matter referred to in clause (a) or sub-clauses (i) and (ii) of clause (f) of sub-section (1), have all the powers of a civil court trying a suit, and in particular, in respect of the following matters, namely :—

- (a) summoning and enforcing the attendance of any person from any part in the State and examining him on oath;

- (b) requiring the discovery and production of any document;
- (c) receiving evidence on affidavits;
- (d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;
- (e) issuing commissions for the examination of witnesses and documents; and
- (f) any other matter which may be prescribed.

(3)(a) On any investigation mentioned in clause (a) or sub-clauses (i) and (ii) of clause (f) of sub-section (1) being completed, the Commission on taking up the matter with the State Government or the appropriate authority under clause (e) or (f) of sub-section (1) may, recommend to the State Government or the appropriate authority, as the case may be, to institute legal proceedings or prosecution in the matter and may also recommend to the State Government or the appropriate authority, to appoint a counsel or a special prosecutor for the conduct of any such legal proceedings or prosecution; and the State Government may, having regard to the nature of the case and on being satisfied that it is necessary, in its opinion, to appoint a counsel or special prosecutor, do so.

(b) The State Government or the appropriate authority, as the case may be, shall communicate in writing to the Commission, from time to time, the progress of any such legal proceeding or prosecution filed on the recommendation of the Commission.

(4) The State Government or the appropriate authority shall not apply for withdrawal of any such case or proceedings instituted under sub-section (3), without the prior consultation, in writing, with the Commission.

Government to consult Commission.

11. The State Government shall consult the Commission on all major policy matters affecting women.

Power of Commission to utilise the service of certain officers and investigation agencies for conducting investigation.

12. (1) The Commission may, for the purpose of conducting investigations under this Act utilise the services of,—

- (a) any officer or investigation agency of the State or the Central Government with the concurrence of that Government ; or
- (b) any other person.

(2) For the purpose of conducting an investigation, any officer or agency referred to in clause (a) of sub-section (1) may, subject to the direction and control of the Commission,—

- (a) summon and enforce the attendance of any person and examine him;
- (b) require the discovery and production of any document; and
- (c) requisition any public record or copy thereof from any office.

(3) Such officer or agency or the person shall investigate into the matter as directed by the Commission and submit a report thereon (hereinafter, in this section, referred to as "the investigation report"), to the Commission within such period or extended period as may be specified or extended by the Commission in this behalf.

(4) The Commission shall satisfy itself about the correctness of the facts stated and the conditions, if any, arrived at in the investigation report submitted to it under sub-section (3), and for this purpose the Commission may make such inquiry (including the examination of the person or persons who conducted or assisted in the investigation) as it thinks fit.

13. No statement made by a person in the course of giving evidence before the Commission or an officer, or agency, referred to in clause (a), or the person appointed under clause (b), of sub-section (1) of section 12, shall subject him to, or be used against him in, any civil or criminal proceeding except a prosecution for giving false evidence by such statement ;

Statements made by persons to Commission.

Provided that the statement, —

- (a) is made in reply to a question which as required by the Commission or such officer or agency or such person to answer, or
- (b) is relevant to the subject matter under investigation.

14. (1) Any voluntary organisation for women within the State may seek registration with the Commission for the purposes of the Act. The Commission may, after satisfying itself in the manner deemed fit by the Commission about the value and role of such organisation in the society, include the name of such organisation in its register.

Registration of voluntary organisations and seeking their assistance.

(2) The Commission may maintain a register of voluntary organisations within the State and more particularly women's organisations whose assistance it may seek for the discharge of its functions.

(3) In discharge of its functions, the commission may seek the assistance of any voluntary Organisations within the State, more particularly, the women's organisations.

(4) A list of such organisations registered with the Commission shall be made available to any court or authority, or, on request, to the members of general public.

(5) If, for any reasons to be recorded in writing, the Commission deems it fit to cancel the name of any organisation from its register, it may do so, after giving such organisation a reasonable opportunity to be heard.

(6) The decision of the Commission about such cancellation shall be final.

15. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any member of the Commission or any officer or other employee of the Commission or any person acting under the direction either of the State Government or of the Commission, in respect of any thing which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule or order made thereunder.

Protection of act done in good faith.

16. (1) The State Government shall, after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, pay to the Commission by way of grants from the Consolidated Fund of the State, such sums of money as the State Government may think for being utilised for the purposes of this Act.

Grants by State Government.

(2) The Commission may spend such sums as it thinks fit for performing the functions under this Act, and such sums of money shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub-section (1).

Accounts and audit.

17. (1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed by the State Government in consultation with the Accountant General of the State of Himachal Pradesh.

(2) The annual accounts of the Commission shall be audited by the Accountant General of the State at such intervals as may be specified by him and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Commission to the Accountant General.

(3) The Accountant General and any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Commission under this Act, shall have the same rights and privileges and the authority in connection with such audit as the Accountant General generally has in connection with the audit of Government accounts and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the Commission.

(4) The accounts of the Commission, as certified by the Accountant General or any other person duly appointed or authorised by him in this behalf, together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the State Government, by the Commission.

Annual report

18. The Commission shall prepare, in such form and at such time for each financial year as may be prescribed, its annual report, giving a full account of its activities during the previous financial year and forward a copy thereof to the State Government.

Annual report and audit report to be laid before State Legislature.

19. The State Government shall cause the annual report and all the reports under clauses (b), (m) and (n) of sub-section (1) of section 10 together with the memorandum of action taken or proposed to be taken on the recommendation contained therein, in so far as they relate to the State Government and the reasons for the non-acceptance, if any, of such recommendations, and the audit report, to be laid as soon as may be after the reports are received, before the State Legislature.

Chairperson, Members etc. to be public servants.

20. The Chairperson, the members, officers and other employees of the Commission shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

Power to make rules.

21. (1) The State Government may, by notification in Official gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) Every rule made under this Act, shall, as soon as possible, after it is made or issued, be laid on the table of the Legislative Assembly and if, before the expiry of the Session in which it is so laid or the next session, the Assembly makes any modification in any such rule or notification or the Assembly decides that rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done or omitted to be done under that rule.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Experience in our country has shown that the Government machinery remains burdened with a variety of problems especially when it comes to developmental work in the social sector, more particularly, women's development. It is, therefore, most essential to set up a high powered body at the apex level to examine policies, review legal safeguards for women, redress grievance and to oversee/evaluate implementation of schemes. The National Commission for Women Act, 1990 was passed by Parliament, keeping in view these considerations. In view of this it has been considered necessary to set up State Level Commission for Women under the law enacted by the State Legislature.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

VIDYADHAR,
Minister-in-Charge.

SHIMLA :
The 2nd December, 1996.

FINANCIAL MEMORANDUM

Sub-clause (5) of clause 4 and sub-clause (2) of clause 5 of the Bill provides for the payment of honorarium, salaries and allowances to the Chairperson and the Members of the Himachal Pradesh State Commission for Women and the officers and other employees of the Commission. Under clause 6, read with clause 16, the administrative expenses, salaries and allowances payable to the Chairperson, Members, Officers and other employees of the Commission shall be paid out of the grants by the State Government. The proposal to constitute the State Commission for Women will involve an expenditure of rupees 23.41 lacs initially and recurring expenditure of rupees 16.41 lacs per annum which shall be met by way of grants to be given to the said Commission out of the consolidated funds of the State of Himachal Pradesh.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 21 of the Bill empowers the State Government to make rules for carrying out the provisions of the Bill. Under clause 9 of the Bill the Commission is required to regulate its own procedure. The rules to be made by the State Government are to be laid before the Legislative Assembly. The proposed delegations are essential and normal in character.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Welfare Department File No. Kalyan-F (2) 2/88-II]

The Governor of Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh State Commission for Women Bill, 1996, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.

